भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-219
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगारी स्तर से संबंधित आंकड़े

219. श्री एंटो एन्टोनीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बेरोजगारी स्तर से संबंधित कोई आंकड़ा है;
(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास गत 12 महीनों के दौरान रिपोर्ट की गई संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार छिनने और रोजगार सृजन से संबंधित संख्या का कोई महीना-वार आंकड़ा है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में रोजगार सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी की दर नीचे दी गई है:

सर्वेक्षण*	बेरोजगारी दर
2018-19 (पीएलएफएस(	5.8%
2017-18 (पीएलएफएस(	6.0%
2015-16 (श्रम ब्यूरो(	3.7%
2013-14 (श्रम ब्यूरो(	3.4%
2012-13 (श्रम ब्यूरो(	4.0%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

(ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार-बरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2018-19 के दौरान आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर एवं कामगार जनसंख्या अनुपात क्रमशः 5.8% एवं 35.3% था।

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

भारत सरकार ने 20 लाख करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की हिमायत की है, यह बेरोजगारी को कम कर सकता है और देश में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है।

*****